

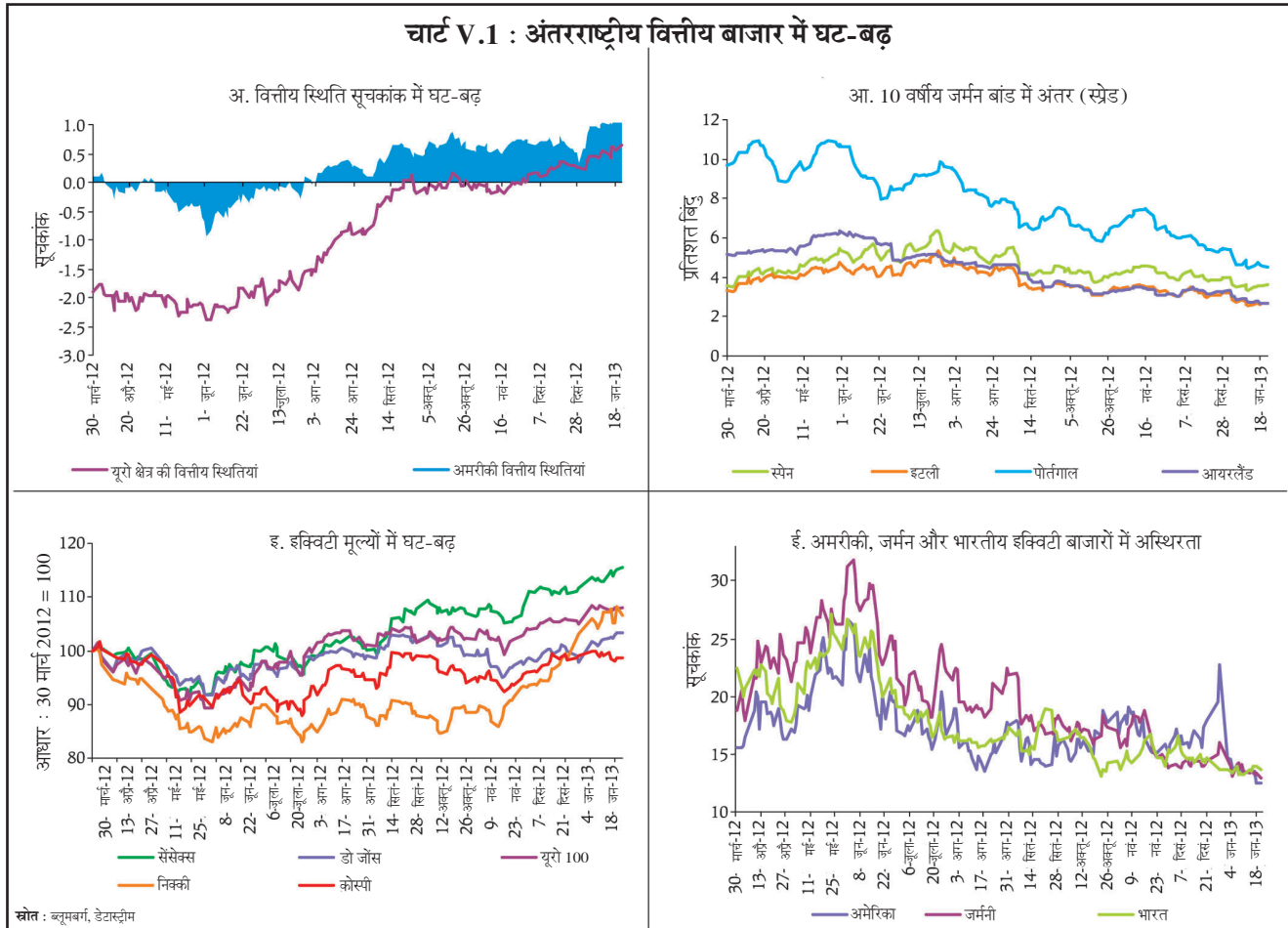
V. वित्तीय बाजार

देशी और वैश्विक-दोनों स्तरों की नीतिगत कार्रवाई का प्रभाव 2012-13 की ति3 के लिए अच्छा रहा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक सुगमता के लिए किए गए उपायों और संकटग्रस्त यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में किए गए नीतिगत उपायों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाहों में तेजी आ गई। निवेशकों के विश्वास में सुधार होने से भारतीय रुपया और इक्विटी बाजारों को काफी लाभ मिला। देशी समष्टिआर्थिक तनाव के बावजूद, अर्थव्यवस्था में सुधार होने की आशा से भारतीय बाजारों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। आईपीओ बाजार में एक वर्ष की मंदी के बाद तेजी आने से निवेशकों के विश्वास में सुधार होना स्पष्ट हुआ।

यूरो क्षेत्र की नीतिगत कार्रवाई और राजकोषीय क्लिफ समझौते के आधार पर वैश्विक वित्तीय बाजारों में सुधार हुआ

V.1 दुर्बल वैश्विक आर्थिक संभावना के बावजूद 2012-13 की ति3 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार की स्थिति में सुधार हुआ। वित्तीय बाजार की हाल की गतिविधियों से पता चलता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख अधोमुखी जोखिमों में कमी आई है। तनाव में कमी ब्लूमबर्ग संयुक्त वित्तीय स्थिति सूचकांक द्वारा प्रदर्शित सकारात्मक संकेत से देखी जा सकती है जिसमें मुद्रा, बांड और इक्विटी बाजारों के समग्र तनाव को ध्यान में लिया गया है जिससे ऋण की उपलब्धता और लागत का आकलन किया जा सकता है (चार्ट V.1अ)।

V.2 नीतिगत नई घोषणाओं और आसपास की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से यूरो क्षेत्र का संकट अल्पकालिक रूप से बदतर होने की संभावना भी कम हो गई है। दिसंबर 2012 में यूरो क्षेत्र के वित्तीय मंत्रियों



ने यूरोपीय केंद्रीय बैंक को 2014 से सामान्य बैंक पर्यवेक्षक के अधिकार दिए हैं। उन्होंने स्पेनिश बैंक के लिए € 39.5 बिलियन की सहायता का अनुमोदन भी दिया। अंतरराष्ट्रीय नेतागण अधिक मार्जिन (हेयर कट) के साथ ग्रीस के ऋण के पुनर्निर्धारण पर भी सहमत हो गए जिससे सहायता भुगतान के लिए € 34.4 बिलियन जारी करने का रास्ता साफ हो गया। इन गतिविधियों से यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऋण चूक स्वैप का अंतर कम हो गया।

V.3 वित्तीय बाजारों में उधार की स्थिति में सुधार होने से स्पेन, इटली, आयरलैंड और पुर्तगाल जैसे यूरोप के संकटग्रस्त देशों और जर्मनी के बीच का 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति ब्याज दर अंतर कम हो गया (चार्ट V.1आ)। निधियन की स्थिति में सुधार होने से इटली और स्पेन की सरकारें भी बाजारों से दीर्घावधि ऋण जुटाने की स्थिति में थीं।

V.4 वैश्विक इक्विटी मूल्यों में 2012 में काफी वृद्धि हुई क्योंकि प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मात्रात्मक प्रोत्साहन घोषित करने से निवेशकों ने कंपनी आय में कमी के बावजूद जोखिमयुक्त आस्तियों को अपने पास रखने को तरजीह दी थी। अमरीका द्वारा किए गए लघु राजोषीय समझौते के कारण भी 2013 में अब तक वैश्विक बाजारों में सुधार हुआ (चार्ट V.1इ)। निहित अस्थिरता के आधार पर नापी गई शेयर बाजार की अस्थिरता भी समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम हो गई (चार्ट V.1ई)।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों के अपारंपरिक नीतिगत प्रोत्साहन से बाजार में तेजी आई

V.5 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा दिए गए अपूर्व मौद्रिक प्रोत्साहनों, जिनमें क्यूई3 और यूएस फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा 45 बिलियन अमरीकी डॉलर की दीर्घावधि खजाना प्रतिभूतियों के अतिरिक्त क्रय की हाल की घोषणा, ईसीबी द्वारा तत्काल मौद्रिक लेनदेन कार्यक्रम और बैंक ऑफ जापान द्वारा आस्ति क्रय कार्यक्रम और साथ ही यूरो क्षेत्र के संकट को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा किए गए उपाय शामिल हैं, से वैश्विक वित्तीय वातावरण को प्रोत्साहन मिला। इसके अनुरूप, इन केंद्रीय बैंकों के तुलनपत्रों में काफी विस्तार हुआ (चार्ट V.2)।

V.6 केंद्रीय बैंकों की अपारंपरिक मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई के सकारात्मक प्रभाव के बावजूद ऐसी नीति के भावी प्रभाव के संबंध में चिंता उत्पन्न हुई है क्योंकि क्यूई के बाद के दौर

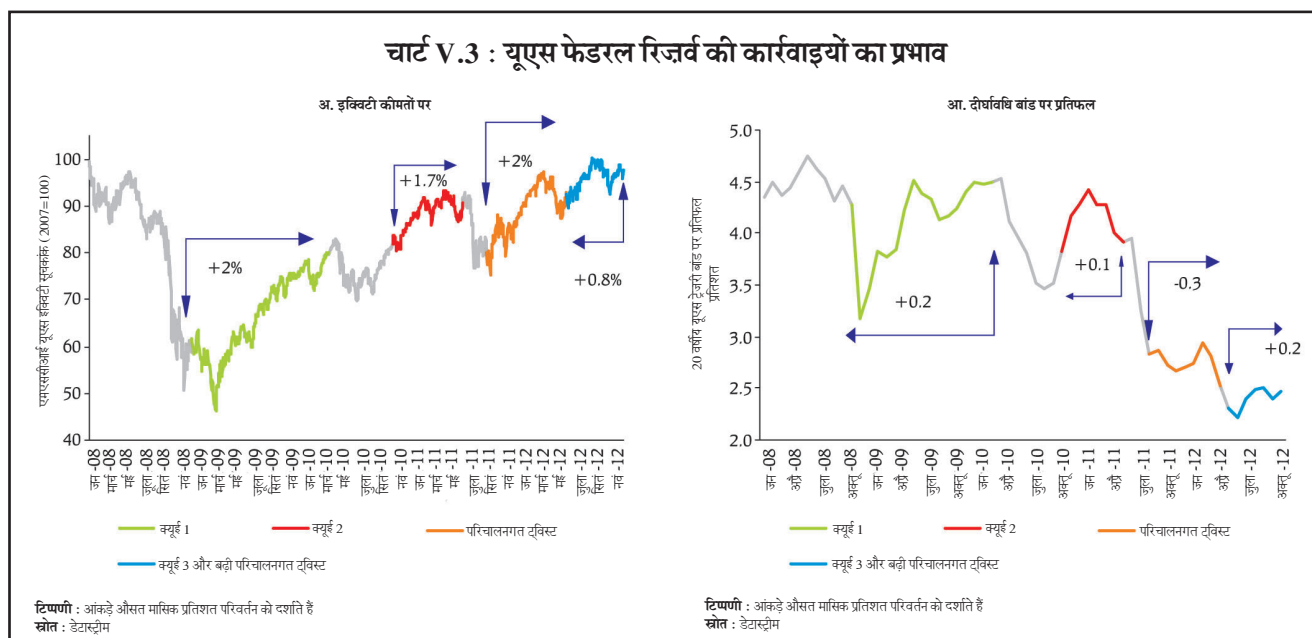


का प्रभाव कम रहा था (चार्ट V.3अ)। 2012 की ति4 का मौद्रिक नीतिगत प्रोत्साहन अमरीका में दीर्घकालिक खजाना आय को कम नहीं कर सका (चार्ट V.3आ)। इसका कारण यह हो सकता है कि एक विश्वसनीय दीर्घकालिक राजकोषीय सुदृढीकरण योजना के अभाव में केंद्रीय बैंक की कार्रवाई के प्रति आय ने कम प्रतिसाद दिया होगा। कुल मिलाकर, क्यूई की सफलता के आकलन के लिए और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है।

पूंजी प्रवाह में उछाल से ईएमडीई में आस्ति मूल्यों में तेजी आ गई

V.7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनायी गई सरल मौद्रिक नीति से उभरी अत्यधिक वैश्विक चलनिधि के साथ निवेश के अवसरों की कमी के कारण यह निधि अधिक प्रतिलाभ की खोज में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में पहुंच गई। भारत और अन्य एशियाई देशों जैसे कि दक्षिण कोरिया, फिलीपीन्स और थाईलैंड को 2011 की तुलना में 2012 में अधिक विदेशी संस्थागत निवेशक अंतर्वाह प्राप्त हुआ (चार्ट V.4)।

V.8 उल्लिखित पुश फैक्टर के अलावा, देशी कारणों से उभरते विभिन्न पुल फैक्टरों, जैसे कि निर्यात-प्रेरित अन्य अर्थव्यवस्थाओं से भिन्न भारतीय अर्थव्यवस्था का देशी उपभोग पर निरंतर निर्भर रहना और सूचीबद्ध कंपनियों की तुलनात्मक रूप से स्थिर आय के कारण भारत में अधिक अंतर्वाह हुआ।



सरकार द्वारा सितंबर 2012 के मध्य से घोषित देशी सुधार के उपायों से भी निवेशक प्रेरित हुए। भारतीय इक्विटी बाजारों में काफी सुधार हुआ जबकि रुपया दायराबद्ध बना रहा।

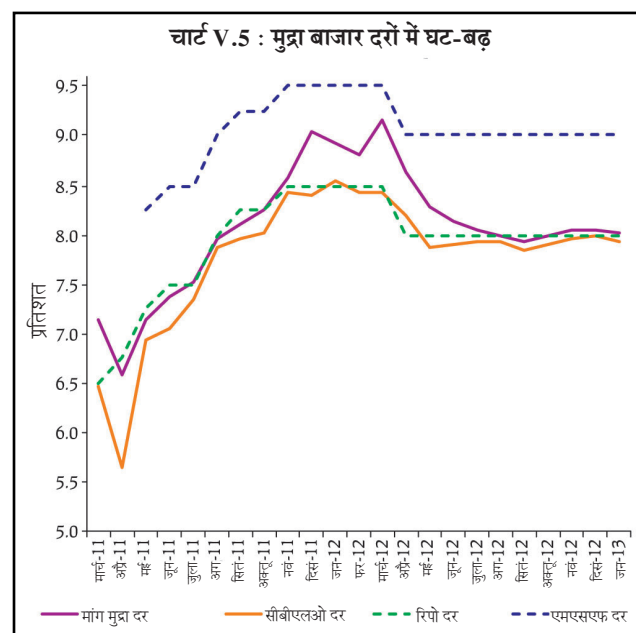
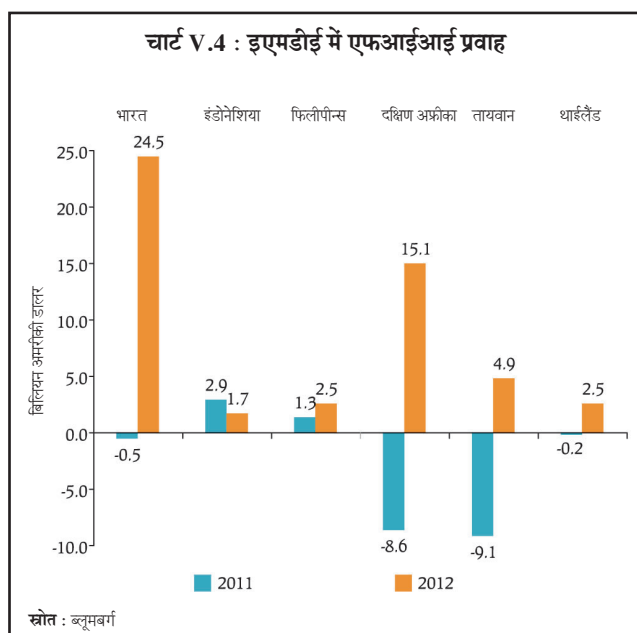
चलनिधि की कमी के बावजूद मुद्रा बाजार स्थिर बने रहे

V.9 अग्रिम कर भुगतान, उच्च सरकारी नकदी शेष और संचलनगत मुद्रा में वृद्धि के बावजूद 2012-13 की ति3 में भारित औसत मांग मुद्रा दर सामान्यतः रिपो दर के आसपास बनी रही। संपाश्रित घटकों अर्थात् सीबीएलओ और बाजार रिपो, जो कि

एक दिवसीय मुद्रा बाजार का मुख्य हिस्सा होते हैं (लगभग 80 प्रतिशत), की दरें मांग मुद्रा दर के अनुरूप रहीं (चार्ट V.5)।

V.10 बकाया जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) की राशि में 2012-13 के दौरान कमी आई। कुल सीडी निर्गम की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर मार्च 2012 के अंत के 11.1 प्रतिशत से कम होकर दिसंबर 2012 के अंत में 8.7 प्रतिशत रह गई (सारणी V.1)।

V.11 बैंकों द्वारा कंपनी क्षेत्र को उधार देने की जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ने, जैसा कि ऋण-उठाव में नरमी और साथ ही वाणिज्यिक पत्रों के पाक्षिक निर्गम में हुई काफी वृद्धि से



सारणी V.1 : देशी वित्तीय बाजार में औसत दैनिक मात्रा

(₹ बिलियन)

| माह | मुद्रा बाजार | | | | | | बांड बाजार | | फोरेक्स बाजार अंतर-बैंक (बिलियन अमरीकी डॉलर) | स्टॉक बाजार ### |
|----------|--------------|-------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------|
| | एलएएफ | मांग मुद्रा | रिपो बाजार | सीबीएलओ | वाणिज्यिक पत्र* | जमा प्रमाणपत्र* | सरकारी प्रतिभूति** | कॉरपोरेट बांड# | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| मार्च-12 | -1574 | 175 | 112 | 380 | 912 | 4195 | 99 | 26 | 21 | 152 |
| जून-12 | -913 | 152 | 180 | 376 | 1258 | 4252 | 258 | 30 | 19 | 117 |
| सित्त-12 | -517 | 143 | 185 | 502 | 1706 | 3572 | 260 | 36 | 21 | 143 |
| अक्तू-12 | -671 | 150 | 218 | 436 | 1941 | 3531 | 230 | 39 | 20 | 139 |
| नव-12 | -941 | 141 | 207 | 368 | 1994 | 3066 | 157 | 25 | 18 | 128 |
| दिसं-12 | -1231 | 142 | 147 | 398 | 1818 | 3328 | 197 | 28 | 19 | 145 |

*: बकाया की स्थिति।

**: केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की औसत दैनिक एकमुश्त मात्रा बिक्री।

: कॉरपोरेट बांड की औसत दैनिक बिक्री।

: बीएसई एवं एनएसई में औसत दैनिक व्यापार।

टिप्पणी: एलएएफ के अंतर्गत दिए गए आंकड़े (-) प्रणाली में चलनिधि के अंतर्वेशन की ओर संकेत करता है।

भी देखा जा सकता है। कुल सीपी निर्गम की भारांकित औसत बढ़ा दर मार्च 2012 के अंत के 12.2 प्रतिशत से कम होकर दिसंबर 2012 के अंत में 9.0 प्रतिशत रह गई।

आर्थिक मंदी के चलते और उधारी कार्यक्रम की स्थिति ठीक रहने से आय वक्र अधोमुखी रहा

V.12 2012-13 की ति3 के दौरान सरकारी प्रतिभूती आय में अक्तूबर में वृद्धि हुई किंतु दिसंबर से इसमें काफी गिरावट आई क्योंकि चार प्रमुख कारणों से बांडों में तेजी आई थी। पहला, बाजार के अनुमान के अनुसार वर्ष में अतिरिक्त बाजार उधार की संभावना नहीं थी। दूसरा, कम होती मुद्रास्फीति के कारण दर कटौती की संभावना बन गई थी। तीसरा, रिजर्व बैंक द्वारा ओएमओ क्रय की शुरुआत से सरकारी प्रतिभूति बाजार में तेजी आ गई। चार, सरकार की नकदी की स्थिति की समीक्षा के बाद, दिनांकित प्रतिभूतियों की 4 जनवरी 2013 को होने वाली नीलामी फरवरी 2013 तक आस्थगित की गई; इसके कारण भी आय में कमी आई। 10-वर्षीय जेनेरिक आय मार्च 2012 के अंत के 8.63 प्रतिशत से कम होकर 1 जनवरी 2013 को 7.99 प्रतिशत और 24 जनवरी 2013 को 7.88 प्रतिशत रह गई (चार्ट V.6)।

V.13 किंतु, ति3 के दौरान अल्पकालिक आय में गिरावट अधिक नहीं थी जिसका मुख्य कारण चलनिधि की कमी की निरंतरता और राजकोषीय वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान खजाना बिल निर्गम की मात्रा बढ़ाने का निर्णय था। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति और 91 दिवसीय खजाना बिलों की आय का अंतर नकारात्मक हो जाने से सरकारी बाजार का आय वक्र

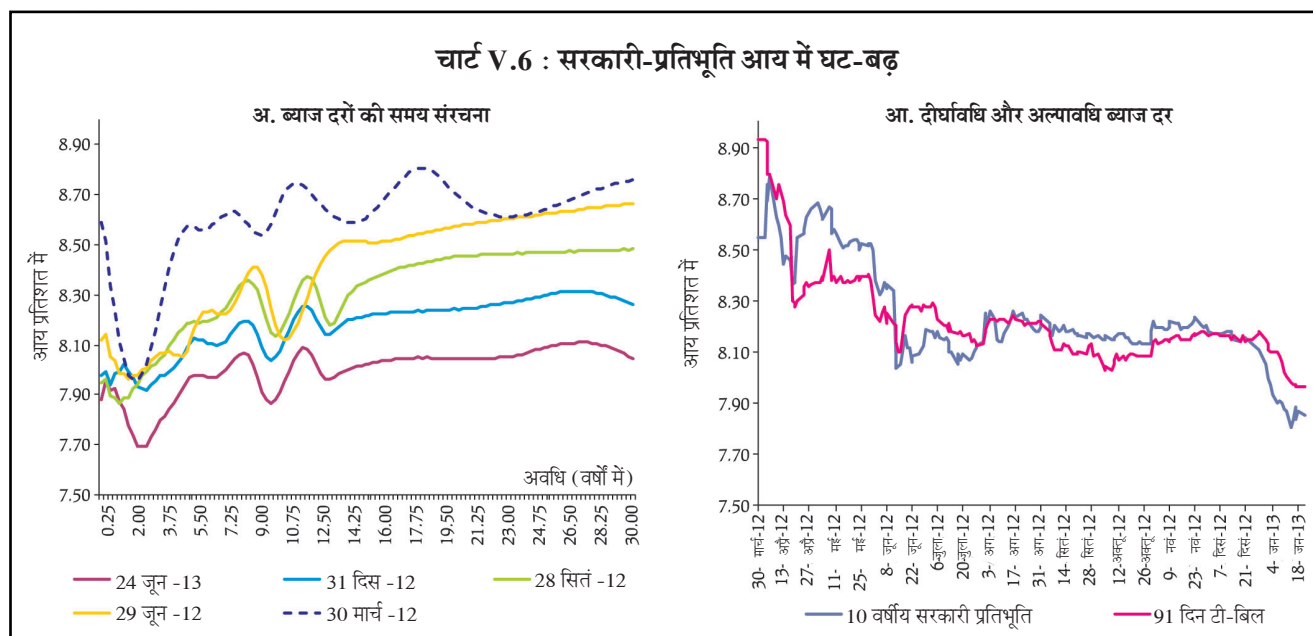
नीचे आने लगा। वित्तीय वर्ष के दौरान 21 जनवरी 2013 तक, जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारांकित औसत परिपक्वता बढ़कर 13.5 वर्ष हो गई जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 12.5 वर्ष थी। बिड-कवर अनुपात 1.36-4.10 के दायरे में बना रहा जो कि पिछले वर्ष 1.39-5.12 के दायरे में था (सारणी V.2)।

V.14 इसी अवधि में, 27 राज्यों ने सकल आधार पर ₹1.3 ट्रिलियन जुटाए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में लगभग ₹1.1 ट्रिलियन जुटाए गए थे।

2012-13 की ति3 में रुपया विनिमय दर दायराबद्ध रही

V.15 कुछ क्षेत्रों के लिए एफडीआई की सीमा उदारीकृत करने सहित सुधार के विभिन्न उपायों और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण योजना की घोषणा से भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक निवेशकों के विश्वास में वृद्धि हुई। इसके साथ ही अमरीकी फेड और बैंक ऑफ जापान द्वारा मात्रात्मक सुगमता की घोषणा से भी भारत में पूंजी अंतर्वाह बढ़ गया और रुपए में सुधार हुआ। सितंबर 2012 में मूल्यवृद्धि के बाद रुपया की गतिशीलता दुर्बलता की प्रवृत्ति के साथ दायराबद्ध हो गई जो कि व्यापक व्यापार घाटे को दर्शाती है (चार्ट V.7)।

V.16 23 जनवरी 2013 को रुपए ने मार्च 2012 के अंत की तुलना में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना जैसी अन्य प्रमुख ईएमडीई की तुलना में कम मूल्यहास दर्शाया (सारणी V.3)।



एफआईआई प्रवाहों के साथ बाजार में चलनिधि में सुधार होने से देशी इक्विटी बाजार में मजबूती आई

V.17 24 जनवरी 2013 को देशी इक्विटी बाजारों में 17.2 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई जिसमें सितंबर 2012 के अंत की तुलना में 6.2 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। सामान्यतः बेहतर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों और नीतिगत कार्रवाई से प्रेरित वैश्विक इक्विटी बाजार की तेजी के कारण भारतीय सराफा में भी तेजी आई। बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी दो वर्षों के बाद क्रमशः 20,000 और 6,000 अंकों को

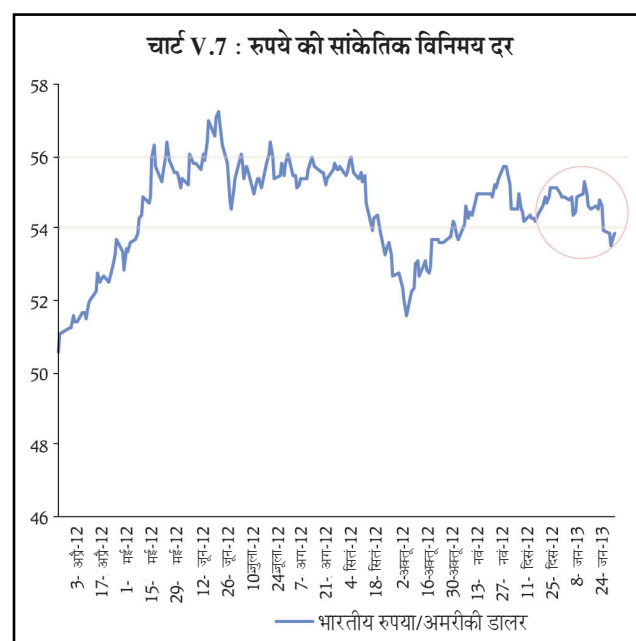
पार कर गए। 24 जनवरी 2013 को बीएसई सेंसेक्स 19,924 पर बंद हुआ।

V.18 डीजल मूल्य वृद्धि, सब्सिडीयुक्त एलपीजी की उच्चतम सीमा, खुदरा और हवाई क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति तथा संसद में बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक पारित होने जैसे हाल के सुधार संबंधी उपायों सहित विभिन्न कारणों और रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी 2013 में नीतिगत दर में कटौती की आशा से और पर्याप्त एफआईआई अंतर्वाहों से देशी इक्विटी बाजार में सुधार होने में सहायता मिली।

सारणी V.2 : केन्द्र एवं राज्य सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम

| मद | 2011-12 | 2012-13* |
|--|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| केन्द्र सरकार | | |
| सकल उधार राशि (₹ बिलियन) | 5,100.0 | 5,220.0 |
| प्राथमिक व्यापारियों का विकास (₹ बिलियन) | 121.1 | 18.3 |
| बोली-कवर अनुपात (रेंज) | 1.39-5.12 | 1.36-4.10 |
| भारत औसत परिपक्वता (वर्ष) | 12.66 | 13.48 |
| भारत औसत आय (प्रतिशत) | 8.52 | 8.39 |
| राज्य सरकार | | |
| सकल उधार राशि (₹ बिलियन) | 1,586.3 | 1,312.3 |
| अधिकतम आय सीमा (प्रतिशत) | 8.36-9.49 | 8.58-9.31 |
| भारत औसत आय (प्रतिशत) | 8.79 | 8.92 |

* 21 जनवरी 2013 तक।



सारणी V.3 : अमरीकी डालर की तुलना में चुनिंदा इएमडीई की विनिमय दरों में घट-बढ़
मूल्यवृद्धि (+)/मूल्यहास (-) प्रतिशत में

| मुद्रा | 2010-11 | 2011-12 | मार्च 2012 के अंत की तुलना में 23 जनवरी 2013 की स्थिति |
|----------------------------------|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| चालू खाता घाटा वाले देश | | | |
| 1. ब्राजिलियन रियाल | 9.7 | -10.8 | -10.4 |
| 2. भारतीय रुपया | 1.1 | -12.7 | -4.9 |
| 3. मैक्सिकन पीसो | 4.3 | -7.0 | 1.2 |
| 4. दक्षिण अफ्रीकी रेंड | 8.0 | -11.5 | -14.3 |
| 5. तुर्किश लीरा | -4.8 | -10.5 | 0.6 |
| चालू खाता अधिशेष वाले देश | | | |
| 1. अर्जेंटीना | -4.3 | -7.5 | -11.7 |
| 2. इंडोनेशियाई रुपया* | 4.7 | -5.1 | -4.7 |
| 3. मलेशियाई रिंगिट | 8.2 | -1.4 | 1.0 |
| 4. दक्षिण कोरियाई वॉन | 2.2 | -2.7 | 6.9 |
| 5. थाई बहत | 6.7 | -1.8 | 3.6 |
| 6. रशियन रबल | 3.4 | -2.8 | -3.0 |
| 7. यूरो | 5.4 | -6.0 | -0.2 |
| 8. चीन | 4.1 | 4.2 | 0.3 |

*: 2011 की चौथी तिमाही से इंडोनेशिया चालू खाता घाटा वाले देशों के वर्ग में आ गया है।

V.19 बाजार पूंजीकरण और दैनिक पण्यवर्त जैसे बाजार संकेतकों ने 2012 में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई जो कि भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसके अलावा, बीएसई सेंसेक्स का पीई अनुपात 2012 में बढ़ गया जो कि भारतीय स्टॉक में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाता है।

V.20 2012-13 के दौरान (23 जनवरी 2013 तक) एफआईआई ने पूंजी बाजार (इक्विटी और ऋण दोनों) में ₹1,190 बिलियन का निवल निवेश किया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹520 बिलियन का निवेश हुआ था। एफआईआई ने इक्विटी बाजार में ₹1,011 बिलियन का निवल निवेश किया जबकि पिछले वर्ष ₹ 27 बिलियन का निवेश किया था।

V.21 देशी संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) (जिनमें बैंक, देशी वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, नई पेंशन निधि

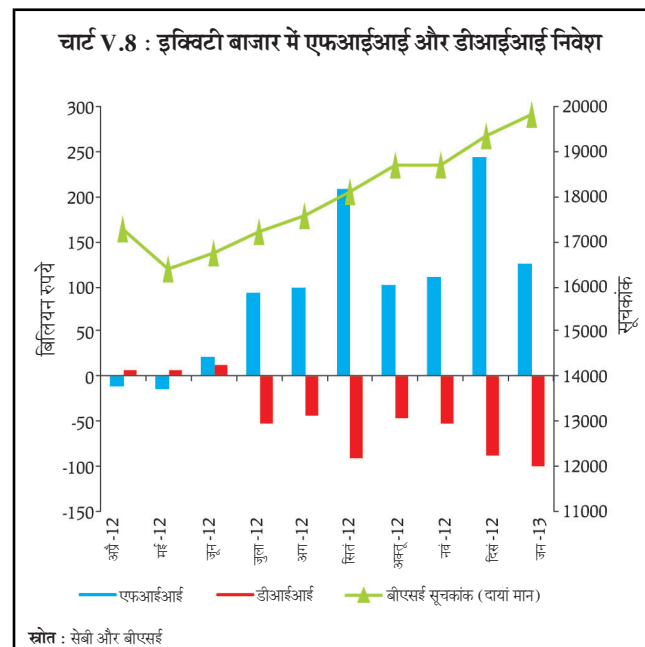
और पारस्परिक निधि शामिल है) ने 2012-13 के दौरान (23 जनवरी 2013 तक) निवल विक्रय किया (चार्ट V.8)।

बैंकेक्स ने सेंसेक्स को पीछे छोड़ दिया

V.22 दिसंबर 2012 के अंत में, कम ऋण वृद्धि, आस्ति गुणवत्ता में गिरावट और जोखिम वृद्धि की चिंताओं के बावजूद बीएसई बैंकेक्स, जो कि भारत में प्रमुख बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने बीएसई सेंसेक्स (26 प्रतिशत) की तुलना में 57 प्रतिशत की उच्च वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। बीएसई बैंकेक्स को अनुकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारकों में निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों की मजबूत स्थिति, सीआरआर में एनडीटीएल के 175 आधार अंकों की कटौती के कारण निवल ब्याज मार्जिन में स्थिरता और बांडों में तेजी के चलते खजाना लाभ की अपेक्षा शामिल है। बैंकेक्स को समग्र भारतीय इक्विटी बाजारों के सकारात्मक दृष्टिकोण का भी लाभ मिला।

आईपीओ बाजार में मंदी के बाद दिसंबर 2012 में सुधार दिखा

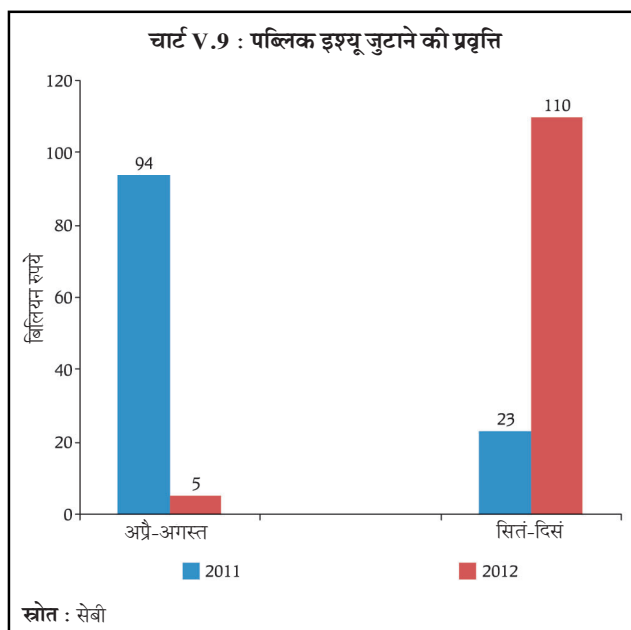
V.23 सितंबर-दिसंबर 2012 के दौरान 18 निर्गमों के माध्यम से ₹110 बिलियन जुटाए गए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 11 निर्गमों से ₹23 बिलियन जुटाए गए थे (चार्ट V.9)। सेबी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों, जैसे कि पात्र विदेशी निवेशकों को प्राथमिक और गौण बाजारों में निवेश की अनुमति देना, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता



जून तक प्राप्त करने की अपेक्षा, राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना, 2012 की शुरुआत और सरकार के विनिवेश कार्यक्रम से भी प्राथमिक बाजार की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।

आवास मूल्यों में मात्रात्मक वृद्धि के साथ कुछ सुधार हुआ

V.24 अखिल भारतीय स्तर पर रिज़र्व बैंक के तमिाही आवास मूल्य सूचकांक में वार्षिक वृद्धि 2012-13 की ति2 में 23 प्रतिशत पर मजबूत बनी रही। किंतु तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि कम होकर 3 प्रतिशत रह गई जो कि पिछले सात महीनों का निम्नतम स्तर था। ति2 में लेनदेन की मात्रा में वृद्धि हुई और इसमें 12 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि हुई (सारणी V.4)।



सारणी V.4 : आवास मूल्य और अंतरण मात्रा सूचकांक (आधार ति 4 : 2008-09 = 100)

| तिमाही | मुंबई | दिल्ली | बंगलुरु | अहमदाबाद | लखनऊ | कोलकाता | चेन्नै* | जयपुर | कानपुर | अखिल भारतीय |
|----------------------------------|--------|--------|---------|----------|-------|---------|---------|-------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| आवास मूल्य सूचकांक | | | | | | | | | | |
| ति1:2011-12 | 191.6 | 152.8 | 116.9 | 152.3 | 149.3 | 157.0 | 106.3 | 161.1 | 135.4 | 152.0 |
| ति2:2011-12 | 206.1 | 153.0 | 116.0 | 162.8 | 159.2 | 159.0 | 113.9 | 165.1 | 138.3 | 157.8 |
| ति3:2011-12 | 191.7 | 168.6 | 146.1 | 171.8 | 172.3 | 155.0 | 120.3 | 163.5 | 140.0 | 164.1 |
| ति4:2011-12 | 224.7 | 195.3 | 140.6 | 177.2 | 169.7 | 158.4 | 117.0 | 164.4 | 148.7 | 176.9 |
| ति1:2012-13 | 231.8 | 217.3 | 140.2 | 176.6 | 179.4 | 204.2 | 133.9 | 171.9 | 144.9 | 188.6 |
| ति2:2012-13 | 232.4 | 225.2 | 143.0 | 183.4 | 208.9 | 226.9 | 129.5 | 177.7 | 135.8 | 194.3 |
| वृद्धि प्रतिशत में | | | | | | | | | | |
| व-द-व | 12.8 | 47.2 | 23.2 | 12.7 | 31.3 | 42.7 | 13.7 | 7.6 | ३०1.8 | 23.1 |
| ति-द-ति | 0.3 | 3.6 | 2.0 | 3.9 | 16.4 | 11.1 | ३०3.3 | 3.4 | ३०6.3 | 3.0 |
| आवास अंतरण मात्रा सूचकांक | | | | | | | | | | |
| ति1:2011-12 | 89.5 | 149.4 | 100.8 | 134.3 | 93.9 | 107.9 | 80.3 | 243.1 | 208.4 | 123.2 |
| ति2:2011-12 | 79.0 | 165.5 | 123.5 | 154.1 | 106.7 | 139.2 | 85.5 | 239.1 | 131.1 | 129.1 |
| ति3:2011-12 | 75.9 | 195.9 | 84.6 | 131.2 | 165.1 | 108.9 | 130.9 | 222.0 | 120.6 | 128.9 |
| ति4:2011-12 | 108.6 | 149.8 | 70.8 | 122.2 | 153.0 | 128.5 | 99.0 | 247.5 | 172.1 | 126.5 |
| ति1:2012-13 | 153.2 | 133.6 | 81.6 | 140.1 | 151.9 | 98.2 | 80.9 | 296.7 | 154.9 | 134.6 |
| ति2:2012-13 | 100.4 | 142.6 | 112.6 | 130.5 | 233.7 | 96.9 | 68.2 | 322.6 | 409.2 | 145.4 |
| वृद्धि प्रतिशत में | | | | | | | | | | |
| व-द-व | 27.1 | ३०13.8 | ३०8.8 | ३०15.3 | 119.1 | ३०30.4 | ३०20.2 | 34.9 | 212.1 | 12.6 |
| ति-द-ति | ३०34.5 | 6.7 | 38.0 | ३०6.9 | 53.9 | ३०1.3 | ३०15.7 | 8.7 | 164.1 | 8.0 |

टिप्पणी: *चेन्नै सूचकांक आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों दोनों पर आधारित है। अखिल भारतीय सूचकांक शहरी सूचकांकों का भारित औसत है, भार जनसंख्या के अनुपात पर आधारित है।

बाजारों में सुधार हुआ किंतु 2013 में काफी अनिश्चितता है

V.25 अनेक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय स्थिति में गिरावट और केंद्रीय बैंकों के विस्तारित तुलनपत्रों के कारण मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई की कम गुंजाइश से दृष्टिकोण और बाजार दायराबद्ध बने रहने की संभावना है। यूरो क्षेत्र की अनिश्चितता में कमी आने और अमरीका में राजकोषीय क्लिफ का अस्थायी समाधान निकलने से वैश्विक वित्तीय बाजारों में तनाव कम हो गया। किंतु अमरीका द्वारा विश्वसनीय

राजकोषीय सुदृढीकरण से अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मात्रात्मक सुगमता से भारत सहित ईएमडीई में पूंजी प्रवाह बढ़ गया है जिसमें आगे कुछ कमी आ सकती है किंतु करीबी संदर्भ में यह फिर भी सकारात्मक बने रहने की संभावना है।

V.26 देशी कारकों को देखते हुए, सुधार के लिए प्रतिबद्धता और राजकोषीय सुदृढता की निरंतरता के प्रयासों से बाजारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निवेशकों के आशावाद की सहायता के लिए वैश्विक और देशी सुधार महत्वपूर्ण है।